

प्रगति प्रतिवेदन 2011–12



Tribal Development

Rural Development

Panchayti Raj

Health



Sustainable Livelihood

Climate Change

Human Development

Right Based



Reg.No.IND/2033/95

सर्व हितैषी षिक्षण समिति, झाबुआ

49, षिंद्वेष्वर कालोनी, झाबुआ—457661

मो. 09770295890

ईमेल: jhabuasarvahitaishi@gmail.com

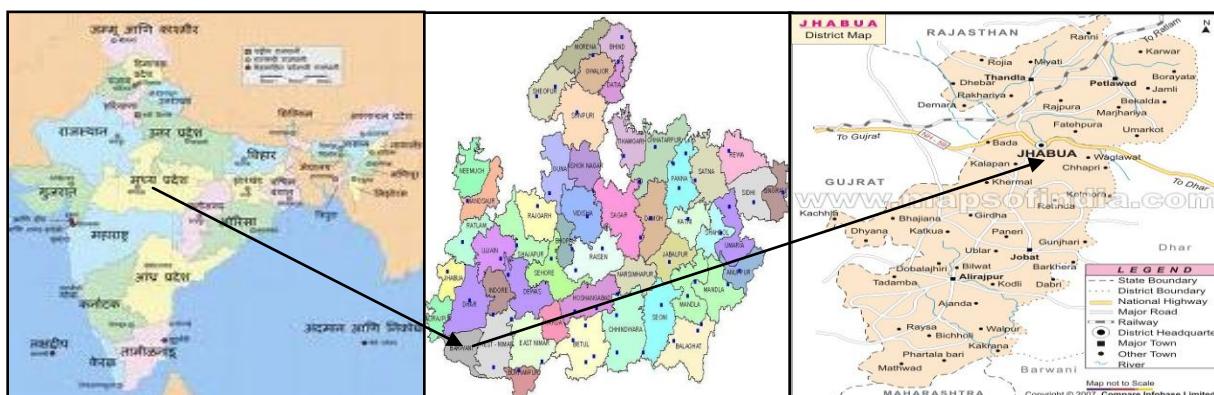
सारणी

विवरण	पेज क्र.
I. प्राकृतिक परिचय	3
II. संस्था का परिचय	4
III. अजीविका का अधिकार	5
IV. स्वास्थ्य	6
V. वन अधिकार अधिनियम एवं मनरेगा	7
VI. पंचायती राज अधिनियम	8
VII. संस्था की जानकारी	9
VIII. संस्था की संरचना	10

प्राकृतिक परिचय

झाबुआ जिला इन्दौर संभाग के अंतर्गत म.प्र. दक्षिण-पश्चिम छोर पर स्थित है। आदिवासी बहुल इस जिले के उत्तर में इन्दौर अहमदाबाद, राजस्थान और रतलाम जिले हैं। पूर्व में धार जिला तथा दक्षिण में खरगोन व महाराष्ट्र की सीमायें इसे छुती हैं संपूर्ण झाबुआ जिला 6 विकासखण्डों में विभाजित है। सभी विकासखण्डों में आदिवासियों की छितरी हुई बसाहट है। सामान्य परिभाषा के अनुरूप यहां कोई भी गांव वास्तविक रूप से गांव नहीं है। प्रत्येक गांव दूर-दूर बनी झोपड़ियों के अनेक समूहों में 3-5 कि.मी. क्षेत्र में फैला रहता है। संस्था द्वारा चयनित क्षेत्र जिले के झाबुआ विकासखण्ड में स्थित है। यहां निवासरत जनजातियों में प्रमुख भील, भिलाला, व पटलिया हैं। भीलों की तुलना में पटलिया अधिक विकसित माने जाते हैं। शराब का सेवन यहां की संस्कृति में शामिल है। भगोरिया और गल का त्यौहार यहां बड़े उत्साह से मनाया जाता है।

झाबुआ जिला पहाड़ी क्षेत्र है। जो विध्यांचल तथा मालवा के पठारी क्षेत्र में है। झाबुआ एक सूखा ग्रस्त क्षेत्र है, जहां कि औसत वर्षा 786 प्रतिषत है, और जिसमें से 29 से 37 तक की परिवर्तनीयता है। सतही जल का कोई सतत स्रोत नहीं है तथा भुमिगत, जल का स्तर भी अत्यंत कम है। जिले में अधिकांश भूमि पथरीली है। अल्प सिंचाई व्यवस्था के कारण वर्ष में केवल एक फसल ही ठीक से ली जा सकती है। यहां बोई जाने वाली फसलों में मक्का, चावल, गेहूं कुछ तिलहन व कपास प्रमुख हैं। कृषि में लाभ के अंष का गिरना, जिले में एक हालात पैदा कर रहा है, परिणामस्वरूप वे लोग जो खेती में निर्भरता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, मजदुरों की जमात में शामिल होने के लिए मजबूर हैं। यहां के अधिकांश किसानों के पास बहुत कम भूमि है। वर्ष में एक फसल लेने के पश्चात अकट्टूबर से जून माह तक वे अन्य राज्यों में मजदूरी हेतु पलायन कर जाते हैं। बड़े पैमाने पर होने वाले मौसमी पलायन ने बच्चों की शिक्षा प्रभावित की है। इसी कारण साक्षरता में जिला पिछड़ा है। झाबुआ के आदिवासी का पलायन लाभ के उद्देश्य से नहीं है वरन् यह तो गरीब आदमी की स्वयं को बचाने की मजबूरी है।



संस्था परिचय

सर्व हतैषी षिक्षण समिति की स्थापना सन् 1995 में स्थानिय, सामाजिक गतिविधीयों को संचालित करने बाले लोगों के द्वारा की गई थी। झाबुआ जिला आदिवासी समुदाय का होकर पिछड़ा हुआ है, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था व सामाजिक कुरीतियां समाज को एकजुट करने में बाधक हो रही है। इन सारी बातों को कैसे दूर किया जाए एवं कैसे यहाँ का सर्वांगिन विकास हो इस पर पर एकमत होकर संस्था अनेक कार्य कर रही है। यहाँ अस्थाई / स्थाई रूप से किये गये कार्यों को देखकर उनसे जो अनुभव मिला, उनमें परिवर्तन करते हुए स्थानिय भाषा, स्थानिय परम्परा, स्थानिय अर्थव्यवस्था को देखते हुए एवं लोगों के अधिकार के लिये लडते हुए लोगों को प्रेरित कर, अजीविका, अधिकार, स्वास्थ्य, षिक्षा एवं आदिवासी समाज की परम्परा को लेकर समाज को प्रगतिषील बनानें का कार्य जारी है।



अजीविका का अधिकार— सरकार
द्वारा लोगों की अजीविका सुनिश्चित करने के लिये अनेकों योजनाओं को लागू किया है लेकिन आदिवासी समुदाय में शिक्षा का अभाव होने के कारण वह उन योजनाओं को समझ नहीं पाते और उन योजनाओं को प्राप्त करने की जानकारी उनके पास न होने के करण वह उन योजनाओं से वंचित रह जाते हैं जो सरकार ने उनके लिये लागू कर रखी है ऐसी

योजनाओं को उन लोगों तक पहुँचाने एवं उन्हे जागरूक करने का कार्य संस्था द्वारा किया जा रही है जिससे गरीब एवं वंचित समुदाय की आजीविका सुनिश्चित हो सके चाहे वह विधवा पेंशन की योजना हो वृद्धा पेंशन योजना, विकलांग पेशन योजना, कृषि आधारित योजना एवं अन्य योजनाओं की लोगों को जानकारी देकर जागरूक कर इन योजनाओं का लाभ वंचित समुदाय को दिलाने का कार्य संस्था द्वारा किया जा रहा है।

अजीविका की सुनिश्चिता आज के समय में प्रत्येक परिवार के लिये आवश्यक है जिसके लिये संस्था द्वारा किसानों को कृषि विकास की योजनाओं से जोड़ किसानों को एक मंच पर एकत्रित करने के लिये किसानों की बीज सहकारी समितियों का गठन ग्राम स्तर पर किया जा रहा है जिससे स्वयं किसानों द्वारा अच्छे स्थानीय बीज का उत्पादन किया जाये और उस बीज से लम्बे समय तक उत्पादन प्राप्त कर स्थानीय बीज को बड़ोतरी दी जाये। जिसके माध्यम से किसान समिति के माध्यम से बीज प्रमाणीकरण बेच सकते हैं और कृषी विभाग की योजनाओं का लाभ लेकर कई कृषी सम्बन्धि कार्य कर सकते हैं।

स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उन्हे अपनी आजीविका प्राप्त करने योग्य बनाने का कार्य भी संस्था द्वारा किया जा रहा जिससे प्रत्येक वंचित समुदाय की आजीविका को सुनिश्चित किया जा सके। संस्था द्वारा 40 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है जिसके माध्यम से 450 सदस्य संगठनों में जुड़कर छोटी छोटी बचत करके आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। समय समय पर समूह से सदस्यों द्वारा ऋण लिया जाता है जिससे वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समस्याओं के समाधान करते हैं और छोटे व्यवसायों से जुड़कर संषक्त हो रहे हैं। इसके अतरिक्त समूह के माध्यम से सदस्य घासकीय योजनाओं से जुड़कर उनका लाभ ले रहे हैं।

स्वास्थ्य

टी.बी. जागरूकता:— संस्था के द्वारा सी.बी.सी.आई कार्ड के सहयोग से रानापुर ब्लॉक के सभी गाँव में अक्षया प्रोजेक्ट के अन्तर्गत टी.बी.जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका उद्देश्य है कि लोगों को टी.बी. की बीमारी के बारें में जागरूक कर गाँवों को टी.बी. मुक्त बनाना। जिसके अन्तर्गत संस्था द्वारा रानापुर ब्लॉक के प्रत्येक गाँव में गठित ग्राम स्तरिय समितियों जैसे ग्राम स्वास्थ्य तदर्थ समिति, ग्राम पंचामत समिति, एवं गाँव के जिम्मेदार व्यक्तियों के साथ मीटिंग कर उन्हे टी.बी. के बारें जागरूक किया जा रही है जिससे बह अपने गाँव में टी.बी. के बचाओं के लिये कार्य कर सके साथ साथ गाँव में ऐसे लोग दो सप्ताह से ज्यादा खाँसी से ग्रसित हैं और वह व्यक्ति जो टी.बी. के संधिगद मरीज लगते हैं उनकी जाँच कराकर पीड़ित पाये जाने पर डॉट्स का इलाज सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र से कराया जा रही है साथ साथ टी.बी. संधिगद लोगों को जाँच के लिये स्वास्थ्य केन्द्र पर रेफर कर जाँच की सलाह देकर प्रेरित किया जा रहा है और ऐसे मरीज जो जाँच के लिये स्वास्थ्य केन्द्र तक नहीं जा सकते उन लोगों की खकार लेकर संस्था के कार्यकर्ता जाँच के लिये स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुंचाते हैं इस प्रकार से रानापुर ब्लॉक के 30 गाँव में इस प्रकार से कार्यक्रम किये जा चुके हैं।



स्वास्थ्य शिविर:— गाँव मे फैल रही बीमारियों का समय समय पर ध्यान रखते हुए संस्था द्वारा स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया जिसमे कई बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर इलाज के लिये जिला अस्पताल से इलाज कराया गया इस कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग का सहयोग लेकर इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन संस्था द्वारा किये जाते हैं एवं इस कार्यक्रम में तराशी स्त्रोत केन्द्र भोपाल के द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है झाबुआ जिले में ऐसे क्षेत्र जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएँ आसानी से नहीं मिल पाती उन जगहों पर शिविर का आयोजन किया गया।



पेक्स परियोजना (पुअरेस्ट एरिया सिविल सोसायटी) –मुद्दा वन अधिकार अधिनियम एवं मनरेगा

पेक्स परियोजना डी.एफ.आई.डी. के सहयोग से रानापुर लॉक के 44 गाँव में संचालित की जा रही रही है जिसमे संस्था द्वारा वन अधिकार अधिनियम एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के बेहतर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये कार्य कर रही है पेक्स परियोजना का उद्देश्य है कि लोग अपने अधिकारों के लिये स्वयं आवाज उठाएँ और उन्हे प्राप्त करें।

जल,जंगल,जमीन और प्राकृतिक संपदा पर आदिवासीयों का कई बर्षों से अधिकार चला आ रहा है जिस जंगल,जमीन पर रहकर वह उसकी रक्षा करते हैं और उसी से अपनी आजीविका चलाते हैं आज उसी अधिकार से उन्हे वंचित किया जा रहा है और वह जमीन व अधिकार उनसे छीने जा रहे हैं उन अधिकारों को दिलाने के लिये संस्था द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं, वन क्षेत्रों में जहाँ वास्तविक रूप से उस जमीन के हकदार हैं उन लोगों को जागरूक कर अधिकार पत्र दिलाने के लिये आवेदन कर उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिये कार्य किया जा रहा है। ग्राम वन अधिकार समिति जो वन अधिकार अधिनियम की एक महत्वपूर्ण इकाई ग्राम स्तर पर उनकी क्षमतावृद्धि प्रशिक्षण किये जा रहे हैं जिससे वह वन अधिकार अधिनियम मे अधिकारों की सुनिश्चिता हेतु अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।

परियोजना के अन्तर्गत अब तक इस वर्ष मे 40 स्वयं सहायता समूहों का गठन अलग अलग गाँव में किया गया है संस्था द्वारा उन समूहों की वन अधिकार अधिनियम एवं मनरेगा पर प्रशिक्षण कर क्षमतावृद्धि का कार्य किया जा रहा है जिससे लोग समूह में जागरूक होकर अपने अधिकारों की माँग कर सकें एवं स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिये योजनाओं से जोड़कर आत्मनिर्भर

वनाया जा रहा है इस वर्ष मे 200 से अधिक लोगों को मनरेगा मे काम की माँग करने एवं काम दिलाने का कार्य किया गया है। स्वयं सहायता समूह एक ऐसी इकाई है जिसमे गाँव के लोग एक मंच पर जुड़कर अपनें अधिकारों की माँग कर सकते हैं और अपनी आजीविका सुनिश्चित कर सकते हैं समूह के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का कार्य किया जा रहा है जिससे मलिलाएँ स्वयं अपने अधिकारों के लिये आगे आ सकें।



पंचायती राज अधिनियम:— पंचायती राज अधिनियम 1992 में बनाया और और जिसमे ग्राम पंचायत को गॉव की सर्वोच्च इकाई माना गया और अनुसूचित क्षेत्रों की ग्रामसभा को विशेष अधिकार दिये गये लेकिन 20 वर्ष गुजरने के बाद के बाद पंचायती राज को नियम से गॉव में लागू नहीं किया जा रहा आज भी गॉव मे लोग ग्रामसभा का मतलब नहीं समझते हैं और ग्रामसभा के अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं हैं जिससे आज भी लोग अपने मुद्दों एवं फैसलों को ग्रामसभा में नहीं रख पाते हैं।

सर्व हितैषी शिक्षण समिति एवं तराषी स्ट्रोत केन्द्र के सार्थक प्रयासों से झाबुआ ब्लॉक के 6 पंचायतों भीमफलिया, नवागांव, ढेवर, देवजिरी, खेडी एवं डूंगरालालू में ग्राम पंचायत सशक्तिकरण का कार्य कर रही है संस्था द्वारा 6 पंचायतों से 60 लोगों को चयनित किया और उनके साथ ग्रामसभा सशक्तिकरण का कार्य कर रही है जिसके अन्तर्गत चयनित लोगों को प्रशिक्षित किया गया जिससे वह अपने गॉव की ग्रामसभा मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके और साथ साथ गॉव के और लोगों का ग्रामसभा के लिये आगे ला सके। ग्रामसभा की भूमिका, ग्रामसभा के अधिकार, ग्रामसभा के नियम एवं ग्रामसभा में लोगों की भूमिका को जानकर ग्राम नवागांव के लोग ग्रामसभा के लिये पूरी तरह से सशक्त हो गये हैं और ग्रामसभा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

आदिवासी क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार अधिनियम 1996 (पेसा कानून) एवं श्ध्यप्रदेश अनुसूचित क्षेत्रों की ग्रामसभा (गठन सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम 1998 के अन्तर्गत अलग ग्राम सभा गठन के बारे में आदिवासी समुदाय को जानकरी देकर ग्रामसभा गठन कर आदिवासी परम्पराओं जैसे परम्परागत न्याय प्रणाली एवं जल, जंगल जमीन पर अधिकार पर समुदाय को सशक्त कर आदिवासी समुदाय के पारम्परिक अधिकारों के लिये झाबुआ जिले में कार्य कर रही है क्योंकि पेसा कानून ही एक ऐसा रास्ता है जिससे आदिवासी समुदाय को उनके वास्तविक अधिकार मिल सकते हैं।



संस्था की जानकारी

Registration	IND/2023/95 Dated 05.04.1995
Contact Person	Azhar Ulla Khan (Secretary)
Contact No.	09770295890, 08959619004
Registered Address	49, Sidheswar Colony, Jhabua 457661 M.P.
E-Mail	jhabuasarvahitaishi@gmail.com
FCRA	063320017 Dated 07.05.2004
PAN	AAEAS7272H
12A	Yes
Other Registration	Exempted Under Income TaxAct 1967, (80G) 5(VI)

अनुदानकर्ता संस्था

Funding Agency	Project
DFID	PACS Project for FRA and MGNREGA
CBCI- CARD	Axshaya Projct for T.B. Awerness

साथी संस्थाएँ

आदिवासी चेतना शिक्षण सेवा समिति, झाबुआ

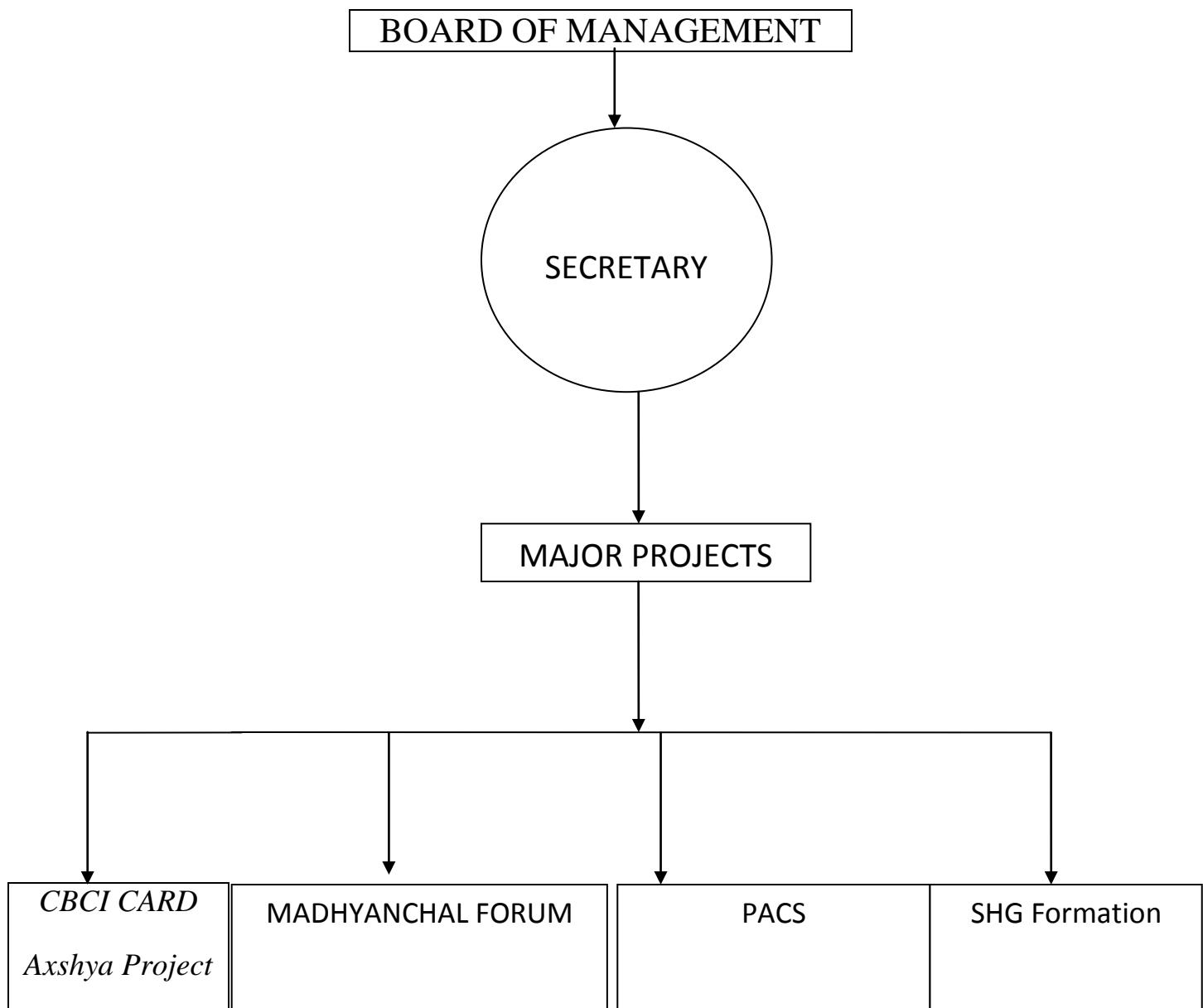
तराशी स्ट्रोत केन्द्र, भोपाल

मध्यांचल फोरम

लोक आजीविका अधिकार महासंघ, म.प्र.

ORGANISATION STRUCTURE

SARVA HITAISHI SHIKSHAN SAMITI



Tkans for Your Kind Support